लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 16- 31 अक्तूबर, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 76

"सनातन के आधार पर ही यह विश्व संचालित हो रहा है।"

: मोहन भागवत

एशियन गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

2

अध्यापकों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लोकप्रिय

5

दक्षिणी हरियाणा की सभी माइनरों की टेलों पर पहुंचा पानी

7

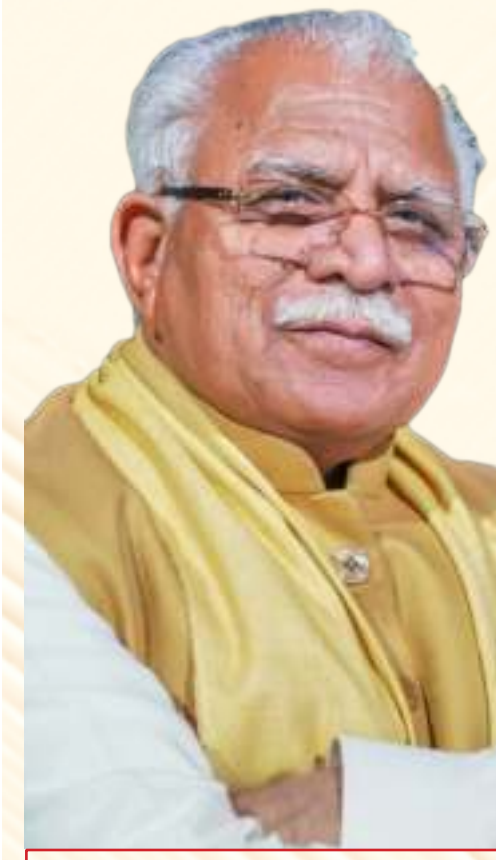

समर्पण और संकल्प

मनोहर योजनाओं से बदली हरियाणा की तस्वीर

अंत्योदय

- योग्यता के आधार पर नौकरी
- ऑनलाइन स्थानांतरण नीति
- ऑनलाइन सरकारी कामकाज
- सीएम विंडो व पोर्टल
- लाल डोरा मुक्त योजना
- ई-टेंडर प्रणाली
- पढ़ी-लिखी पंचायतें
- अमृत सरोवर योजना
- हर घर-नल से जल
- सिंचाई परियोजनाएं
- भावांतर भरपाई योजना
- एमएसपी पर खरीद
- मेरा पानी-मेरी विरासत
- बिजली की उपलब्धता
- मेडिकल कालेज
- समावेशी शिक्षा नीति
- उद्योग नीति
- खेल नीति
- भ्रष्टाचार उन्मूलन
- सबका साथ-सबका विकास

मनोज प्रभाकर

नीयत साफ हो तो हर कार्य में बरकत होती है। उसमें यह भी स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं होती कि किस समय, किस आदमी से, क्या वादा किया गया था। काम के प्रति समर्पण व संकल्प। नित काम-बिना आराम, कोई मुख्यमत्री श्री मनोहर लाल से सीखे। कर्त्तव्य के प्रति उनकी समर्पित भावना एवं प्रतिबद्धता अनूठी व बेजोड़ है। कहते हैं जब घर का मुखिया ईमानदार व मेहनती हो तो परिवार में अच्छे संस्कार स्वतः स्थापित होने लगते हैं।

विगत नौ साल के काल में हरियाणा प्रदेश में कुछ इसी प्रकार की नींव रखी जा चुकी है। सूबे के लोग उस कालखंड को करीब-करीब भूल गए हैं जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर अलग-अलग शक्लों में भेदभाव होता था। भेदभाव से समाज में वैमनस्य पनपता है।

अमन चैन और विकास सबको सुकून देता है, यह सबको चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास के जरिए प्रदेश में इन्हीं संभावनाओं को प्रतिस्थापित करने का बीड़ा उठाया है जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे हैं।

मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर लाल जमीनी हकीकत से रूबरू थे। वे यहां की असमानताओं, अव्यवस्थाओं व सामाजिक विसंगतियों से वाकिफ थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ करीब से देखा था जो उनके मानस पटल पर अंकित था। वे अपने समाज व प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने मूल कार्यों को विराम देते राजनीति में पदार्पण किया। चुनाव लड़ा, सफल रहे और सौभाग्य से सरकार के मुखिया बन गए।

मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी नीतियों का ऐलान कर दिया था। हालांकि निराशा की गर्त में डूबे लोगों को सफलता की उम्मीद कम थी लेकिन आज उन्हीं नीतियों की बदौलत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नजर आ रहा है। फ़र्क साफ है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं, यह पूरा प्रदेश उनका अपना परिवार है। और वे नहीं चाहते कि उनके परिवार का एक भी व्यक्ति गुरबत में जीये। हर परिवार आत्मनिर्भर हो। इसलिए उन्होंने अति गरीब परिवारों को तलाशने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया है।

काबिलियत के आधार पर नौकरी व स्थानांतरण नीतियों ने तो राजनीति के मायने ही बदल दिए हैं। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के दफ्तर लगने लोगों की भीड़ छंट चुकी है।

साल बदलाव के

ऑनलाइन राजकीय कामकाज ने तो प्रदेश के लोगों का जीवन सहज व सरल ही कर दिया है। अब उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए बाबुओं की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ती। कोई भी जन सीएम विंडो पर सीएम के सामने अपनी बात रख सकता है। पढ़ी-लिखी पंचायत व ई टेंडर प्रणाली ग्रामीण व शहरी विकास की नई इबारत लिखने चल पड़ी है।

बीज से बाज़ार तक किसानों के साथ खड़ी मनोहर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरने का काम किया है। खेत खलिहान की हर योजना पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र व कल कारखानों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति एक सपना थी, जो आज साकार है। सेहत के मामले में मुख्यमंत्री की जागरूकता कोरोना काल में ही ज्ञात हो गई थी। राज्य में जिला स्तर पर मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सा संस्थान खोले जा रहे हैं। अब इन संस्थानों में न डाक्टरों की कमी है और न दवाओं की। चिरायू योजना के तहत मुफ़्त उपचार की सुविधा है।

शिक्षा क्षेत्र को समावेशी बनाया गया है। उद्योग नीति से प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है तथा खेल नीति की बदौलत पूरे जगत में हरियाणा ने डंका बजाया है। महिला सुरक्षा एवं सशाक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इन सबके अलावा मनोहर सरकार ने 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा' की नीतियों पर चलते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला है। बिना किसी समझौते के अनेक छोटे-बड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गर्दन को नापा गया है।

देश की अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान देने वाले हरियाणा को आज न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में पहचान मिली है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठकों की विषय सूची में स्थान मिलने लगा है। ऐसा हो भी क्यों न, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष भी तो इसी प्रदेश की पावन धरा कुरुक्षेत्र से हुआ था।

G20 भारत 2023 INDIA

बाढ़ प्रभावितों को मिला मुआवजा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावितों के खाते में मुआवजे की 5 करोड़ 90 लाख 99 हज़ार की राशि अग्रेषित कर दी है। 40 मृतकों के परिजनों को कुल एक करोड़ 60 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। शेष 7 मृतकों के सत्यापन का कार्य जारी है। अब तक बाढ़ प्रभावितों को 7 करोड़ 50 लाख 99000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। फसल के नुकसान की भरपाई का जल्द ही निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। राज्य भर से 1,41,079 किसानों से करीब 6,87,077 एकड़ क्षेत्र में हुए फ़सल के नुकसान का दावा आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा घरों की क्षति के मुआवजे के लिए 7,504 आवेदन प्राप्त हुए।

मेयर हुए ताकतवर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगमों के मेयर को और ताकतवर बनाते हुए प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया है। इसके अलावा काम में लापरवाही करने वाले वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित करने का अधिकार भी दिया गया है।

उन्होंने कहा केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की तरफ से नगर निगमों को तीसरी तिमाही का लगभग 600-700 करोड़ रुपया आवंटित किया जाना है। मेयर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का अनुमान तैयार करें और शीघ्र सरकार को भिजवाएं। विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

मीडिया कर्मियों की बढ़ी पेंशन

प्रदेश में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवरेज को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढाकर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे अब 10 लाख रुपए तक के बीमा पर प्रीमियम की शत प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस फैसले से राज्य के 1038 मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने पात्र मीडियाकर्मियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 10,000 रुपए से बढाकर 15,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति, 2023 को भी मंजूरी प्रदान की है जिससे सोशल मीडिया को विज्ञापनों के लिए सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

संपादकीय

पराली पर नियंत्रण

पराली पर इस बार कड़ी नज़र रखी जा रही है मगर हरियाणा-पंजाब व आसपास के राज्यों से अभी भी यह क्रम किसी स्तर पर जारी है। हरियाणा में इस बारे पराली जलाने के मामले काफी घटे हैं और सरकार कृतसंकल्प है, इस बारे में जागरुकता फैलाने के लिए। अर्थव्यवस्था, अन्य दो सेक्टरों उद्योग और सेवा क्षेत्र जितनी डायनेमिक नहीं होती। इसका कारण है किसानों में जोखिम लेने की क्षमता का कम होना। लेकिन अगर इससे कृषि ठहर जाए तो किसानों के साथ योजनाकारों को भी सोचना पड़ेगा। धान के कटने और उस खेत को गेहूं के लिए तैयार करने का समय आ गया है। देश के अनाज का कटोरा कहलाने वाले राज्यों पंजाब और हरियाणा में बगैर खर्च धान के ठूंठ (पराली) हटाने के लिए किसान फिर खेत में आग लगाने लगे हैं। वर्षों से सरकारें, कृषि वैज्ञानिक और आम जनता की कोशिश है कि पराली न जलाई जाए, क्योंकि इससे निकले धुएं से हवा में प्रदूषण फैलता है। कार्बन के अनेक यौगिक दिल्ली और आसपास के क्षेत्र मे लाखों-करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आग से ज़मीन की नमी भी खत्म होती है और किसानों को ज़्यादा पानी खेत को देना होता है। खेत की उर्वरा शक्ति भी घटती है। किसानों को ये छिपे नुकसान देरी से समझ आ रहे हैं। पंजाब-हरियाणा में गेहूं-चावल की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से लगभग दूनी है लेकिन किसानों को इसके लिए भूगर्भ में संचित जल का दोहन करना पड़ रहा है। एमएसपी पर सबसे ज़्यादा खरीद इन दो राज्यों से होती है लिहाजा किसान अन्य फसलों की ओर रुख नहीं कर रहा

डॉ. चन्द्र त्रिखा

प्रोत्साहन

- राई में हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना ।
- हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का गठन ।
- तीन राज्यस्तरीय खेल स्टेडियम, 21 जिला स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, 25 उप-मण्डल स्तरीय खेल स्टेडियम, 163 ग्रामीण खेल परिसर, 245 मिनी ग्रामीण स्टेडियम तथा 1100 खेल नर्सरिज व 24 आवासीय खेल अकादमी है।
- खिलाड़ियों के लिए 10 डे-बोर्डिंग और 8 आवासीय खेल अकादमियां खोली गई।
- ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए एडवांस दिये जाते हैं।
- अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिमाह किया गया।
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेताओं को 20 हजार रुपए प्रतिमाह और भीम पुरस्कार विजेताओं को 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की शुरुआत की गई।
- खिलाड़ियों को नौकरी के लिए 550 नए पद सृजित किये गये तथा नौकरियों में क्लास वन तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 216 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई।
- पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार व अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु 'हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट फंड' का गठन किया गया है।
- वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा 128 पदक जीतकर देश में दूसरे स्थान पर रहा।

216 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी

हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई खेल नीति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर व खिलाड़ियों को मुहैया करवाई जा रही सुविधाओं की बदौलत प्रदेश के खिलाड़ी विश्व पटल पर हरियाणा का नाम चमका रहे हैं। प्रदेश में खेलों का एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि आज हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार राशि दी जा रही है। इसके अलावा, प्रशिक्षण के साथ-साथ खिलाड़ियों की खुराक में भी किसी प्रकार की कोई कमी न रहे इसके लिए खिलाड़ियों को प्रतिदिन 400 रुपए खुराक राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार की खेल नीति की बदौलत आज प्रदेश खेलों में अपने स्वर्णिम दौर में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार खेलों के लिए व्यवस्था को बेहतर करने, खिलाड़ियों को बेहतर माहौल देने के लिए काम कर रहे है। पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है, जिसके तहत अब तक खिलाड़ियों को 335 करोड़ रुपए से अधिक के नकद पुरस्कार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 9 साल में 216 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। जबकि खिलाड़ियों को नौकरी के लिए 550 नए पद सृजित किए है। खिलाड़ियों को नौकरी में क्लास वन तक आरक्षण का प्रावधान किया है।

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को सबसे अधिक 6 करोड़ रुपए इनाम राशि देने वाला हरियाणा ही है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता खिलाड़ी को डेढ़ करोड रूपए व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को 75 लाख रुपए नकद पुरस्कार दे रही है। प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप साढ़े सात लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है ।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

खेल-खिलाड़ी

» एशियन गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
» हरियाणा की खेल नीतियों का बजा डंका

भारत की पदक तालिका

पदक	व्यक्ति गत	टीम	कुल
स्वर्ण	9	19	28
रजत	23	15	38
कांस्य	26	15	41
कुल	58	49	107

हरियाणा की पदक तालिका

पदक	व्यक्ति गत	टीम	कुल
स्वर्ण	2	7	9
रजत	1	4	5
कांस्य	11	5	16
कुल	14	16	30

संगीता शर्मा

चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्तूबर तक हुए 19वें एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। हरियाणा के खिलाड़ियों का इसमें विशेष योगदान रहा जिसकी पूरे देश भर में प्रशंसा हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की प्रशंसा में लिखा 'एशियाई खेलों में भारत के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। देश के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 107 पदक जीते, यह पिछले 60 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत व अटूट संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है।

भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 पदक अपने नाम किए। इसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। यह एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने 2018 में सबसे ज़्यादा 70 पदक जीते थे। वहीं, स्वर्ण पदक जीतने के मामले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार इतिहास रचा है। अब तक भारत ने एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा 16 स्वर्ण 2018 में जीते थे। इस बार भारत ने 28 स्वर्ण जीतने में सफलता हासिल की है। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे देशभर के कुल 655 खिलाड़ियों में से 85 खिलाड़ी हरियाणा से रहे।

एशियाई खेलों में भारत ने पहली बार 107 पदक खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। इनमें से 33 खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत व टीम स्पर्धा में पदक हासिल किए हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 5 रजत और 16 कांस्य पदक जीते। 17 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीता, जबकि 16 खिलाड़ी टीम इवेंट में पदक लेकर आए।

एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

25 अक्तूबर से गोवा में शुरू होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर हरियाणा ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं।

> चीन में 19वें एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। वर्तमान सरकार ने हमेशा ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आज हरियाणा की पहचान पदक की फैक्ट्री के रूप में बन गई है। इसी का नतीजा है कि अन्य राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने लगे हैं। हरियाणा सरकार की खेल नीति जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें अधिकतम नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए पहचानी जाती है, वहीं खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण आदि सुविधाओं के कारण भी इस नीति की प्रदेशभर में खूब चर्चा होती है। राज्य सरकार की बेहतर खेल नीति के कारण ही एक किसान का बेटा भी विदेश की धरती पर पदक जीतने का दम रखता है।
>
> **- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन

खिलाड़ी	स्पर्धा	पदक
नीरज चोपड़ा	भाला फेंक	स्वर्ण
पलक	निशानेबाजी- महिला (टीम)	स्वर्ण
	(टीम)	रजत
शिवा नरवाल	निशानेबाजी-पुरुष (टीम)	स्वर्ण
सरबजोत सिंह	निशानेबाजी- पुरुष	स्वर्ण
	मिश्रित	रजत
रिथम सांगवान	निशानेबाजी- महिला (टीम)	स्वर्ण
मनु भाकर	निशानेबाजी- महिला (टीम)	स्वर्ण
नितेश कुमार	कबड्डी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
परवेश	कबड्डी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
सुरजीत	कबड्डी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
नवीन कुमार	कबड्डी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
सुनील कुमार	कबड्डी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
नितिन रावल	कबड्डी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
पूजा नरवाल	कबड्डी - महिला (टीम)	स्वर्ण
पूजा काजल	कबड्डी - महिला (टीम)	स्वर्ण
प्रियंका	कबड्डी - महिला (टीम)	स्वर्ण
साक्षी कुमारी	कबड्डी - महिला (टीम)	स्वर्ण
रितु नेगी	कबड्डी - महिला (टीम)	स्वर्ण
सुमित	हॉकी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
अभिषेक	हॉकी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
संजय	हॉकी - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
शाहबाज अहमद	क्रिकेट - पुरुष (टीम)	स्वर्ण
शेफाली वर्मा	क्रिकेट - महिला (टीम)	स्वर्ण
दीपक पूनिया	कुश्ती- पुरुष	रजत
रमिता	निशानेबाजी- महिला (टीम)	रजत
	व्यक्तिगत	कांस्य
संदीप ठकराल	ब्रिज - पुरुष टीम	रजत
सीमा पूनिया	एथलेटिक्स-चक्का फेंक	कांस्य
सुनील कुमार	कुश्ती	कांस्य
अमन सहरावत	कुश्ती	कांस्य
अंतिम पंघाल	कुश्ती	कांस्य
सोनम मलिक	कुश्ती	कांस्य
किरण बिश्नोई	कुश्ती	कांस्य
प्रीति पंवार	मुक्केबाजी	कांस्य
प्रवीण हुड्डा	मुक्केबाजी	कांस्य
नरेंदर बेरवाल	मुक्केबाजी	कांस्य
प्रीति लांबा	एथलेटिक्स-स्टेपलचेज	कांस्य
आदर्श सिंह	निशानेबाजी-पुरुष (टीम)	कांस्य
अनीश भानवाला	निशानेबाजी- पुरुष (टीम)	कांस्य
सविता, उदिता, निशा, मोनिका, नेहा, नवनीत कौर, दीपिका, सोनिका	हॉकी - महिला (टीम)	कांस्य
भजन कौर	आर्चरी-महिला टीम	कांस्य
परमिंदर सिंह	रोइंग-पुरुष	कांस्य
आर्यनपाल सिंह	रोलर स्पोर्ट्स स्पीड स्केटिंग	कांस्य

हरियाणा सिविल सेवा (नियुक्ति की अनुकंपा वित्तीय सहायता)के तहत मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रित को क्लर्क पद पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में कैबिनेट में मंजूरी।

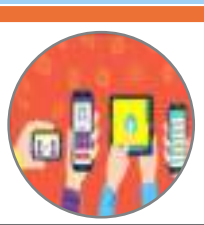

डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को मंजूरी। यह नीति सरकारी नीतियों और कार्य में को उजागर करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया को शामिल करने के उद्देश्य से लाई जा रही है।

डा. चंद्र त्रिखा

अंत्योदय

» 38 लाख नए परिवारों के बने बीपीएल राशन कार्ड

» 50 हजार लोग स्वरोजगार के जरिए हुए आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि प्रदेश का हर परिवार आत्मनिर्भर बने। कोई गरीब न रहे, हर हाथ को काम मिले और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीये। लोगों का जीवन सहज व सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के हर उस परिवार की पहचान की गई है अथवा की जा रही है जो अति गरीब हैं। उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या तो उन्हें राजकीय मदद दी गई है या उन्हें ऐच्छिक कार्य का प्रशिक्षण देकर रोजगार शुरू कराया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय योजना-ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 183.59 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई तथा 42,149 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत 3721.70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई तथा कुल 866.75 लाख कार्य दिवसों का सृजन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिलाओं के कुल 61,713 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया व कुल 381.45 करोड़ रुपए खर्च किए गये।

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत 789 लाभपात्रों को 27 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना'' के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र परिवारों को बीमा और पेंशन के प्रीमियम के रूप में 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पात्र परिवारों को 276 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की आयु तक के सभी बचत बैंक खाताधारकों का 436 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियो में 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के तहत 27.93 लाख लोगों का 26,463 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करवाया गया।

आवास योजना

» प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 67,649 स्वीकृत घरों में से 14,620 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा 15,506 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर। इसके तहत 521.45 करोड़ रुपये की अनुदान राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

» प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 21,673 स्वीकृत घरों में से 21,062 मकान बनाए जा चुके हैं तथा बाकी मकान निर्माणाधीन हैं। इसके तहत लाभार्थियों को कुल 369.38 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जा चुकी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

» डी.बी.टी. के माध्यम से शत-प्रतिशत लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

» परिवार पहचान पत्र से सभी 31.34 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभपात्रों को जोड़ा गया।

» सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक की गई। इस योजना के तहत वार्षिक आय की सीमा भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई।

» अविवाहित पुरुषों, महिलाओं एवं विधुरों को भी अब 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है।

» लाडली पेंशन योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक के माता-पिता, जिनकी सन्तान एक या एक से अधिक केवल लड़कियां हैं, की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक की गई।

» वृद्धावस्था सम्मान भत्ता व दिव्यांग पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है। अब तक 1 लाख 7 हजार वृद्धजनों व लगभग 14,000 दिव्यांगजनों को घर बैठे प्रो-एक्टिव मोड पर पेंशन का लाभ दिया जा चुका है।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण

» मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति और विमुक्त व टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को उनकी बेटी की शादी पर दी जाने वाली शगुन राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 71,000 रुपए की गई।

» सभी वर्गों से गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह हेतु 51,000 रुपए मदद का प्रावधान। शगुन राशि 11,000 रुपए से बढ़ाकर 41,000 रुपए करने का निर्णय।

» अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्र व छात्राओं को विभिन्न उच्च प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग की सुविधा। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को शैक्षणिक भत्ते के रूप में 4000 रुपए वार्षिक दिये जाते हैं।

» डा. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत आय सीमा 4 लाख रुपए वार्षिक की गई। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति का प्रावधान। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत छात्रों को शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस के रूप में 2500 रुपए से 13,500 रुपए वार्षिक तक दिये जाते हैं।

श्रम विभाग

» विभिन्न वर्गों के दिहाडीदार, मजदूरों के न्यूनतम, मासिक एवं दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की गई। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को 1817.18 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।

» काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान। पंजीकृत श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी पर 1,01,000 रुपए की राशि का प्रावधान।

» तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ रहे पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को होस्टल खर्च के लिए 1,20,000 रुपए तक सालाना का प्रावधान।

» पंजीकृत श्रमिकों को उनके मेधावी बच्चों के लिए बोर्ड की दसवीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 21,000 रुपए से 51,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।

» चौकीदारों का मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रतिमाह तथा वर्दी भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिवर्ष किया गया, बैटरी व लाठी भत्ता भी 1,000 रुपए वार्षिक किया गया है।

मानदेय व पेंशन

पद	मानदेय	पेंशन
जिला परिषद अध्यक्ष	10,000 रुपए	2,000 रुपए
जिला परिषद उपाध्यक्ष	7500 रुपए	1,000 रुपए
जिला परिषद सदस्य	3000 रुपए	
पंचायत समिति अध्यक्ष	7500 रुपए	1,500 रुपए
पंचायत समिति उपाध्यक्ष	3500 रुपए	750 रुपए
पंचायत समिति सदस्य	1600 रुपए	
सरपंच	5000 रुपए	1000 रुपए
पंच	1600 रुपए	
सरपंच द्वारा कैश-इन-हैण्ड सीमा	10,000 रुपए	
सफाई कर्मी	14,000 रुपए	

पोर्टल क्रांति

» अटल सेवा केंद्रों के जरिए घर बैठे मिल रहा योजनाओं का लाभ

» ऑनलाइन प्रणाली से भ्रष्टाचार पर लगाम, सीएम विंडो बनी वरदान

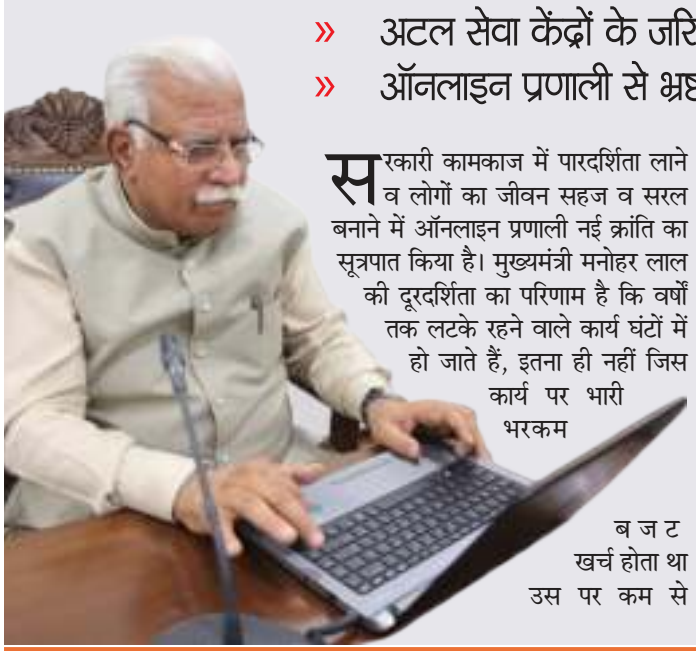

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने व लोगों का जीवन सहज व सरल बनाने में ऑनलाइन प्रणाली नई क्रांति का सूत्रपात किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता का परिणाम है कि वर्षों तक लटके रहने वाले कार्य घंटों में हो जाते हैं, इतना ही नहीं जिस कार्य पर भारी भरकम बजट खर्च होता था उस पर कम से कम खर्च होता है और गुणवत्ता युक्त होता है।

पोर्टल के जरिए सरकार अपनी योजनाओं व सेवाओं को आम आदमी तक पहुचांने में सहज हो गई है तथा लोगों को भी अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, अनेक योजनाओं का फायदा घर बैठे मिल रहा है। किसी नागरिक को किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो उनके लिए सीएम विंडो वरदान साबित हो रही है।

राज्य सरकार ने इसके लिए 22,500 अटल सेवा केन्द्र (15,639 ग्रामीण व 6,861 शहरी क्षेत्र) पंजीकृत किए हैं। सरल पोर्टल के माध्यम से 54 विभागों, बोर्डों व निगमों की 680 सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई हैं। 147 विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा के लिए 5953 गांवों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। गांव हो शहर पैसे के लेन देन का कार्य डिजिटल माध्यम से खूब हो रहा है। सामाजिक पेंशन बैंक खाते में पहुंचते ही फोन पर 'टिन' की आवाज़ लाभार्थी को शुकून दे रही है।

» विभागों के लिए समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील प्रणाली शुरू की गई। इसके तहत 8,47,575 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8,28,029 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

» हर नागरिक अब अपनी समस्या या शिकायत के निवारण के लिए सीएम विंडो के जरिए मुख्यमंत्री से सम्पर्क कर सकता है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भी सीएम विंडो की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विंडो पर लगभग 12 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से करीब 11 लाख शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।

» सीएलयू व जमीनी रजिस्ट्री कार्यों में हेरफेर रोकने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं। इनके अलावा खनन ठेकों में ई-नीलामी और ई-रवाना स्कीम से पारदर्शिता आई है।

» परिवार पहचान पत्र राज्य की महत्वाकांक्षी योजना से हर परिवार को एक अलग परिवार आई.डी दी जा रही है। इससे अंतिम व्यक्ति तक सभी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगा।

पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह की गई है।

पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से प्रत्येक उप-मंडल को एक उप-जिला के रूप में बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

सेहत

» मुफ़्त उपचार के लिए 56 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाये गये

» नौ नए मेडिकल कालेज खोले, एमबीबीएस की सीटें हुई 2185

पहला सुख- निरोगी काया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेहत के मामले में कभी कोई ढिलाई नहीं बरतने दी। कोरोना काल में उन्होंने खुद रात-दिन जागकर लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं मयस्सर कराई। रातों रात न केवल ढांचागत विकास कराया बल्कि दवाइयां, आक्सीजन व अन्य उपकरण भी समय रहते उपलब्ध कराए। उस महामारी का प्रकोप देखते हुए मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था कि स्वास्थ्य की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेना है। उसी संकल्प का परिणाम है कि प्रदेश में जिला स्तर पर मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं ताकि भविष्य में डाक्टरों की कमी न रहे। डाक्टर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए मरीजों की सेवा कर सकें इस तरह की नीतियां बनाई गई हैं।

विगम नौ साल में राज्य सरकार द्वारा 48 उप स्वास्थ्य केंद्र, 46 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 33 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व 17 जिला नागरिक अस्पताल भवन बनाए गए हैं। इन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के अतिरिक्त पर्याप्त दवाइयां भी मुहैया कराई गई हैं। डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 2807 चिकित्सक व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है। सभी सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में 541 दवाइयां, 257 उपभोग्य सामग्री तथा 88 दंत चिकित्सा उपकरण मुफ्त में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। एलोपैथी चिकित्सा के अलावा आयुष को बढ़ावा देने के लिए कई चिकित्सा संस्थान बनाए गए हैं अथवा निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा प्रदेश में 347 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गये हैं।

आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति परिवार उपचार कवर प्रदान किया जाता है। जरूरतमदों को लाभ पहुंचाने के लिए 28 लाख 89 हजार आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 8 लाख दावों के विरुद्ध 910 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस योजना के तहत 749 अस्पतालों (175 सरकारी एवं 574 निजी) को आयुष्मान भारत हरियाणा के साथ सूचीबद्ध किया जा चुका है।

इसी योजना को विस्तार देते हुए चिरायु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ़्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत लगभग 56 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाये गये हैं।

बढ़ते कदम

» प्रदेश में लिंगानुपात की दर वर्ष 2014 में 871 से सुधरकर अगस्त, 2023 में 907 हुई।

» प्रदेश में हेपेटाइटिस बी व सी की दवाईयां व जांच मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है।

» सिटी स्कैन 17 सिविल अस्पतालों में, एमआरआई 5 सिविल अस्पतालों, हैमोडायलिसिस 22 सिविल अस्पतालों और कार्डियोलॉजी सेवाएं 4 केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

» घर पर मुफ़्त चिकित्सा सुविधा के लिए 'ई-संजीवनी ओपीडी' सेवा शुरू।

» घर द्वार पर ही इलाज के लिए 59 मेडिकल मोबाइल यूनिट कार्यरत।

» किसी भी आपात स्थिति के लिए 617 एम्बुलेंस गाड़ियां हर समय उपलब्ध।

» मुख्यमंत्री मुफ़्त इलाज योजना के तहत 7 प्रकार की सेवाएं, नामतः सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, निदान (एक्स-रे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओपीडी/इनडोर सेवाएं, आवश्यक दवाएं, रेफरल परिवहन और दंत चिकित्सा उपचार शामिल हैं।

» हिमोफिलिया, थैलेसिमिया तथा कैंसर के मरीजों को राज्य परिवहन की बसों में मुफ़्त यात्रा सुविधा।

» 13 सिविल अस्पतालों में 100 बिस्तर से 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों में और अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल को 200 बिस्तरों से 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया गया।

» अंबाला छावनी सिविल अस्पताल में कैंसर इलाज के लिए अटल कैंसर देखभाल केंद्र शुरू।

» मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों के स्नातकोश्रर पाठ्य' में में ईडब्ल्यूएस के प्रार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण।

» कुटैल करनाल में 761.51 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर।

» राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाढ़सा का निर्माण 2035 करोड़ रुपए की राशि से किया गया। 710 बिस्तरों का यह संस्थान अमेरिका की एनसीआई की तर्ज पर बनाया गया है।

» हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य के फ्लस्वरूप 9 नये कॉलेज खोले गये। प्रदेश में अब इनकी संख्या 15 हुई।

» मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 2185 और पीजी की सीटें 708 हुई।

» भिवानी में 535.55 करोड़ रुपए, गांव हैंबतपुर, जिला जींद में 663.86 करोड़ रुपए, गुरुग्राम में 500 करोड़ रुपए, कोरियावास, जिला नारनौल में 598 करोड़ रुपए, कैथल में 945.31 करोड़ रुपए, सिरसा में 1089.75 करोड़ रुपए और यमुनानगर में 997.03 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर। पंचकूला, पलवल, फतेहाबाद, चरखी-दादरी में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। छह नर्सिंग कालेज भी बनाए जा रहे हैं।

» 172.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शहीद हसन खान मेवाती सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़, नूंह परिसर में एक दंत महाविद्यालय होगा। गांव छांयसा में भी कालेज बनाया जा रहा है।

» योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग पंचकूला में स्थापित।

» कुरुक्षेत्र में 94.5 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

» माता मनसा देवी, पंचकूला में 20 एकड़ भूमि पर लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान निर्माणाधीन।

» गांव देवरखाना, जिला झज्जर में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित किया जा चुका हैं तथा ओ.पी.डी शुरू।

» बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल पट्टीकरां, नारनौल का निर्माण कार्य पूर्ण। - - प्रदेश का पहला 60 बिस्तरों व 60 सीटों वाला राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल गांव अकेड़ा जिला नूंह में 45.43 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन।

» अम्बाला के गांव चान्दपुरा में 55.85 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पताल निर्माणाधीन।

» गांव मयड़, हिसार में 15 एकड़ जमीन पर 10.85 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों का इंटीग्रेटिड आयुष अस्पताल स्थापित किया जा रहा है।

समाज सेवा को प्राथमिकता दें डाक्टरः राज्यपाल

रोहतक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 7139 विद्यार्थियों को डिग्रियां व 19 मेडल

हरियाणा के राज्यपाल एवं पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने मेडिकल की डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे समाज सेवा को प्राथमिकता दें। समाज प्रत्येक विद्यार्थी की शिक्षा पर प्रतिवर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेज में 11 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च कर रहा है। उन्होंने डॉक्टर को पृथ्वी पर भगवान की संज्ञा देते हुए कहा कि डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर लोगों की सेवा करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।

बंडारू दत्तात्रेय स्थानीय पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सुश्रुत सभागार में तीसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्यातिथि मेडिकल के 7139 विद्यार्थियों को डिग्रियां व 19 मेडल प्रदान करने के उपरांत संबोधित कर रहे थे।

बंडारू दत्तात्रेय ने मेडल व डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके स्वर्ण भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने शोध की जानकारी से अपडेट रहें तथा आधुनिक तकनीक व उपकरणों का प्रयोग करते हुए रोगियों का सेवा भाव से उपचार करें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस विभाग को किसी खेत से ट्रांसफार्मर की चोरी होने पर थानों में बिना समय गवाएं एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। गत 6 महीनों में 32,076 करोड़ रुपए हुआ है, जो 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

शिक्षा

» 74 नए राजकीय कालेज बनाए, जिनमें से 31 लड़कियों के लिए

» अध्यापकों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लोकप्रिय हुई

संगीता शर्मा

हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर में प्रमुखता के साथ लागू किया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने नौ साल के कार्यकाल में शिक्षा के हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर विदेश में रोज़गार के द्वार भी खोले हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने वाले दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली अपना रही है। इसके तहत उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं।

वर्तमान समय सूचना प्रोद्यौगिकी का है और इससे जुड़ने के लिए ई-अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों व उन्हें पढ़ाने वाले पीजीटी को 5.50 लाख टैबलेट्स 2 जी.बी. डेटा के साथ मुफ़्त वितरित किए गये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई। राज्य में सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटिड। 137 नए राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले गये। इनके अतिरिक्त, खण्ड स्तर पर 1,418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय भी खोले गये।

नई शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्य को हरियाणा में वर्ष 2025 तक पूरा करने की उम्मीद है। प्रदेश में कुल 179 राजकीय महाविद्यालय हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 74 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 31 राजकीय महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं। राजकीय महाविद्यालयों तथा राजकीय सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में छात्राओं की स्नातक स्तर तक ट्यूशन फीस माफ़ की गई। 1. 80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की लड़कियों की स्नातकोत्तर स्तर तक टयूशन फीस माफ़ एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए घरौंडा, करनाल में 74 करोड़ रुपए की लागत से एनसीसी अकादमी बनाई जा रही है। राजकीय महाविद्यालयों के यूजी व पीजी के 26,895 छात्रों के निःशुल्क पासपोर्ट बनवाये गये।

अध्यापकों के लिए 'ऑनलाइन स्थानांतरण नीति' लागू की गई है, जिसे देश के अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। अतिथि अध्यापकों की सेवा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक-2019' अधिसूचित किया गया।

मेधावी बच्चों को विशेष कोचिंग

बच्चों और अभिभावकों की टेली-काउंसलिंग के लिए 16 जिलों में उम्मीद केंद्र खोले गये हैं। इसके तहत 2 लाख 6 हजार 150 विद्यार्थियों व अभिभावकों को परामर्श दिया गया। सुपर-100 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को आई.आई.टी, जे.ई.ई. व एन.ई.ई.टी. इत्यादि परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

इसके अलावा सुपर-100 कार्यक्रम की तर्ज़ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सुपर-एनडीए कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को एनडीए की परीक्षा तथा एसएसबी की परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है।

'मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत एव सहायता व अनुदान' (चिराग) योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े पात्र छात्रों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में उनकी सहमति से प्रवेश दिलाया जा रहा है। इसके लिए निजी विद्यालयों को कक्षा दूसरी से पांचवीं तक 700 रुपए, कक्षा 6 से 8 वीं तक 900 रुपए व कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1,100 रुपए प्रति छात्र भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा पर जोर

» वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 15 नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई, जिससे छात्रों की प्रवेश क्षमता में 3,278 की वृद्धि हुई।

» पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में एन.आई.ई.एल.आई.टी.स्थापित किए गए हैं।

» झज्जर में एस.आई.ई.टी, रेवाड़ी में एस.आई.ई.टी. तथा नीलोखेड़ी, करनाल में एस.आई.ई.टी. की स्थापना की गई है। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय डिजाइन सस्थान शुरू किया गया।

» दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल जिला सोनीपत में 50 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत प्रशिक्षण व शिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

» दुधोला, पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

» 29 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये।

» हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा 31,374 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 630 युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया।

दिव्यांग छात्रों की सहायता के लिए नए कार्यक्रम

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने राज्य में छात्रों की शिक्षा, बुनियादी ढांचे और समग्र कल्याण की गुणवत्ता में सुधार समावेशिता, कौशल विकास और नवाचार पर बल देने के लिए 201,346.71 लाख रुपये आवंटित किए हैं। भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा परिभाषित सात कार्य क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर हरियाणा के 3,893 स्कूलों का चयन किया है। पहले चरण में 124 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को पीएमश्री स्कूलों के रूप में चुना गया था। इन स्कूलों में बदलाव लाने के लिए 8,526.76 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और स्वच्छता सुनिश्चित करने, प्रतिभाओं को निखारने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और छात्रों को तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य के लिए तैयार करने के लिए 1,074.2 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 614 लाख रुपए खर्च कर 4,098 स्कूलों में लड़कियों को सशक्त बनाने व उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य' म के तहत 354 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देने, कोडिंग और रोबोटिक्स गतिविधि सीखाने के लिए 460.2 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

स्कूलों में सैनिटरी पैड के वितरण और निपटान के लिए एसपीवीआई मशीनें उपलब्ध कराने के लिए 1394 स्कूलों को 39500 रुपए प्रति स्कूल के हिसाब 550.63 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें से 350 मशीनों की खरीद कर ली गई हैं और शेष 464 मशीनें खरीदने की प्रक्रिया जारी है।

राज्य सरकार ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

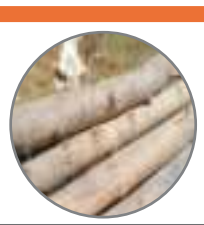

लकड़ी की खरीद पर दो प्रतिशत मार्किट फीस को घटाकर एक प्रतिशत किया है। इससे प्लाईवुड फैक्टरियों के संचालकों को प्रतिवर्ष आठ करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा होगा।

कृषि मेला

हिसार कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय कृषि मेला लगा जिसमें किसानों व कृषि उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित कृषि विकास मेले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। श्री धनखड़ ने आयोजकों के साथ साथ किसानों की मेहनत की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे अत्याधुनिक कृषि तकनीक एवं संयंत्रों की मदद से खेती करने का प्रयास करें। इससे न केवल उनकी आमदन बढ़ेगी देश के आर्थिक विकास में भी सहयोग होगा।

श्री जगदीप धनखड़ ने कहा यदि आप बदलाव लाएंगे, तभी अपना देश 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी का जश्न मनाएगा। तभी भारत विश्व का नंबर-1 देश बनेगा। इसके लिए किसान कृषि उत्पादों के व्यापार के द्वारा उत्पादों में मूल्य वृद्धि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आज लोग सरकारी व निजी कंपनियों से नौकरी छोड़कर कृषि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं और कृषि उत्पादन में अपना हाथ आजमा रहे हैं, जोकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जो उत्पाद किसान पैदा कर रहे हैं उनको बाज़ार में स्वयं बेचने का प्रयास करें।

फ़सल विविधिकरण से आय वृद्धिः मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेले के समापन अवसर पर किसानों से बातचीत में कहा कि पानी की बचत के लिए फसल विविधिकरण आवश्यक हो गया है। इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल को बोने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है। फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीद हो रही है। कुछ फसलों को भावांतर भरपाई के ज़रिए ख़रीदा जा रहा है। अभी बाजरा की फसल को हैफ़ेड द्वारा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर ख़रीदा जा रहा है। सरकार किसानों को इस पर 300 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि फसल पैदावार के साथ उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमें ध्यान देना होगा। प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को रुझान बढ़ाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

सेम ग्रस्त भूमि का सुधारीकरण जोरों परः कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार द्वारा ठोस सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। सेम ग्रस्त भूमि के सुधारीकरण के लिए जितना कार्य पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ उतना कार्य वर्तमान सरकार ने कुछ समय में ही करके दिखाया है। प्रदेश भर में लगभग 8 लाख एकड़ क्षेत्र सेम ग्रस्त है। इस वर्ष 70,000 एकड़ भूमि के सुधारीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जल संरक्षण के लिए खेती में टपका सिंचाई व फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाया गया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार किसानों को 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किसानों की प्रगति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इस विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों, फलों, सब्ज़ियों, तिलहनों, चारा आदि की 284 उन्नत किस्में विकसित करके किसानों को दी हैं, ताकि वे अधिक उत्पादन लेकर ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकें।

लक्की ड्रा से मालामाल हुए किसान

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बटन दबाकर लक्की ड्रा के माध्यम से ईनाम निकाले। इसमें जींद के मोहन खेड़ा गांव के किसान भरत सिंह को 7,50,000 रुपए कीमत का जॉनडीयर ट्रैक्टर, फतेहाबाद के किरढान गांव के अजीत सिंह को 3,50,000 रुपए कीमत का ट्रैक्टर, फतेहाबाद जिले के ही टिब्बी गांव के सुरजीत को 2,50,000 रुपए कीमत की लैंड लेवलर मशीन, पंजाब के गंगा अब्दुल गांव के गुरपिंदर सिंह को 1,75,000 रुपए राशि की सुपर सीडर मशीन तथा जींद जिला के दरोड़ी गांव के किसान अंकित को 74,000 रुपए की कीमत की इलेक्ट्रिक पावर वीडर मशीन मिली।

पर्यटन

» ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू

» गुरुग्राम और नूह में बनेगा विश्वस्तरीय सफारी पार्क

देश की संस्कृतिक विरासत व धरोहर को सहेज कर रखने में पर्यटन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन युवाओं के लिए नए रोज़गार के अवसर भी प्रदान करता है। यही कारण है कि वर्तमान सरकार ने नौ साल के कार्यकाल में पर्यटन को बढ़ावा देने में विशेष ध्यान केंद्रित किया है। गांव की परंपरा से लोगों का जुड़ाव व रू ब रू करवाने के उद्देश्य से फार्म टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क को विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फार्म टूरिज्म पोटेंशियल पर सेमिनार और संभावित गंतव्यों में होम स्टे विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह कार्यक्रम टिक्कर ताल मोरनी हिल्स, पंचकूला में शुरू हुए और गुरुग्राम, यमुनानगर, रेवाड़ी आदि जैसे अन्य जिलों में आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों ने फार्म मालिकों और पर्यटकों की काफ़ी दिलचस्पी जगाई और राज्य में कृषि/ग्रामीण पर्यटन की नींव मजबूत की।

हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में स्थित प्राचीन सन्निहित सरोवर को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए भव्य और सुंदर तीर्थ बनाएगी। इस तीर्थ को विकसित करने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए ही सर्वोच्च बलिदान करने वाले महर्षि दधीचि की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा के पीछे सूर्य और साथ में भगवान इंद्र और वज्र की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।

'स्वदेश दर्शन योजना' के तहत हरियाणा सर्किट की पहचान की गई है। इसके तहत कुरुक्षेत्र को एक मुख्य पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए 97. 34 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि में से 77.87 करोड़ रुपए की राशि, सूचना केंद्र, गैजिबो, पार्किंग, साईनेज बोर्ड, बेंचों, प्रकाश व्यवस्था, शौचालयों, और घाट इत्यादि के निर्माण के लिए जारी की गई।

» हैरिटेज सर्किट रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़-माधोगढ-नारनौल-महेन्द्रगढ़-नारनौल सर्किट के अंर्तगत महेंद्रगढ़ किले के विकास के लिए व रानी महल, बावडी के आंतरिक व बाहरी क्षेत्र के विकास के लिए व माधोगढ़ किले को छोड़कर किले के आस-पास के क्षेत्र को विकसित करने के लिए 29.61 करोड़ रुपए की राशि की परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है।

» सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा हेतु 10,000 रुपयए प्रति तीर्थयात्री, कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु 50,000 रुपए प्रति तीर्थयात्री और गुरु दर्शन योजना के लिए श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा (नंदेड), श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुण्ड साहिब व श्री पटना साहिब हेतु 6,000 रुपए प्रति तीर्थयात्री वित्तीय सहायता दी जा रही है।

» पंचकूला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए टिकरताल, मोरनी हिल्स को साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जैट स्कूटर जैसी ऐरो स्पोर्ट्स और वॉटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां शुरू की गई।

» गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क को विकसित करने का निर्णय लिया गया।

» राखीगढ़ी, हिसार में छह एकड़ क्षेत्र में संग्रहालय एवं विवेचन केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है।

तलाब गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव

विश्व पर्यटन दिवस पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में पर्यटन मंत्रालय द्वारा हरियाणा पर्यटन को ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और देश के 775 गांवों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के तलाब गांव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में मान्यता और पुरस्कार दिया गया है। यह गांव पारंपरिक खेती, बागवानी, खाद और जल संरक्षण को प्रदर्शित करने वाले फार्म टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तलाब के आस-पास के आकर्षणों में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, हरि-वन-औषध वाटिका और नवग्रह वाटिका शामिल हैं, जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट से घिरे हुए हैं।

हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है।

डा.भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के लिए आवेदन करने की तिथि अब 31 जनवरी, 2024 तक की गई है। इसमें दसवीं, बारहवीं व स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

खेत-खलिहान

» भावांतर भरपाई योजना व फसल बीमा योजना बनी नजीर

» दक्षिणी हरियाणा की सभी माइनरों की टेलों पर पहुंचा पानी

संगीता शर्मा

राज्य सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने के साथ-साथ सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। किसानों की खुशहाली में ही प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली निहित है, इसलिए खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं। सरकार फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

- जे.पी दलाल, कृषि मंत्री हरियाणा

हरियाणा के किसान अब अधिक हाईटेक हो चुके हैं और जैविक खेती को अधिक अपना रहे हैं। किसानों को राज्य सरकार के ओर भी विशेष रियायतें दी जाती हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नौ साल के कार्यकाल में किसान हितैषी नीतियों के चलते आज प्रदेश का किसान खुशहाल है। किसानों के समर्थन और उनकी मेहनत के बलबूते हरियाणा कृषि क्षेत्र में क्रांति का अग्रदूत बना है। हरियाणा देश में किसान उत्पादक संगठनों के गठन में सबसे अग्रणी राज्य है। फलों एवं सब्ज़ियों की ग्रेडिंग, भण्डारण व मार्केटिंग के लिए 731 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। इजराइल की तकनीक पर राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य है। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के प्रत्येक लघु किसान परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। यह राशि चौमाही आधार पर तीन किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस योजना के तहत दिसंबर, 2018 से अब तक 19.82 लाख किसानों को 13 किश्तों में 4287.19 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए खरीफ 2016 से 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' शुरू की गई है। इसके अंतर्गत खरीफ में धान, बाजरा, मक्का, मूंग व कपास तथा रबी में गेहूं, सरसों, चना, जौं व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। योजना में खड़ी फसल में जलभराव (धान फसल को छोड़कर) ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा, आसमानी बिजली आदि जोख़िमों को कवर किया गया हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 27.22 लाख किसानों द्वारा उनकी फसल ख़राब होने पर लगभग 7,600 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया।

'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल 4 जुलाई, 2019 से संचालित किया जा रहा है, ताकि किसानों के भूमि रिकॉर्ड और फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जा सके। रबी 2022-23 के दौरान 10 अप्रैल, 2023 तक 8.52 लाख किसानों ने 57.34 लाख एकड़ भूमि पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाया हैं।

पिछले 6 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में सीधे 76 हजार करोड़ रुपए की राशि डाली गई। 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना के तहत धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, खरीफ दालें (अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, सोयाबीन), खरीफ तिलहन (तिल, अरंडी, मूंगफली), चारे की फसल, खरीफ प्याज, बागवानी फसलें/सब्जियां, खाली जमीन तथा सफेदे व पोप्लर द्वारा विविधिकरण करने के लिए शुभारंभ किया गया है। फसल विविधिकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 118 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई है।

पशुपालन

» राज्य के अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के पशुओं का मुफ़्त बीमा। इस योजना के तहत अब तक 9.70 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है। इसके तहत, 14,614 क्लेम के फलस्वरूप लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

» पशुपालकों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 1 लाख 50 हजार से अधिक पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये गये।

» राज्य में 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 2, 4 तथा 10 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाईयां स्थापित करने पर लाभार्थियों को 25 प्रतिषत अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,244 डेयरियां स्थापित हुई हैं।

» देसी गायों के उत्थान हेतु हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालकों को 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

» गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन हेतु एक सशक्त कानून 'हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम-2015' लागू किया गया है। 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के अंतर्गत देसी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं विकास के लिए राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है।

बागवानी

» हरियाणा सभी प्रमुख बागवानी फसलों में 'भावांतर भरपाई योजना' शुरू करने वाला पहला राज्य है। इस योजना के तहत अब तक 12,092 किसानों को 33.26 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जा चुका है।

» नये बाग लगाने पर 25,500 रुपए प्रति एकड़, उच्च सघनता के नये बागों की स्थापना पर 43,000 रुपए तक प्रति एकड़ तथा खजूर के बाग लगाने पर 1,40,000 रुपए तक प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान ।

» फल एवं सब्ज़ियों की ग्रेडिंग, भण्डारण व मार्केटिंग के लिए 731 एफपीओ का गठन।

» इजरायल की तकनीक पर राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्रों में 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित।

» मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 46 बागवानी फसलें शामिल। इस योजना के तहत फलों के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ एवं सब्जियों के लिए 750 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम देना पड़ता है।

» प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल ख़राब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। किसानों की फसलें ख़राब होने पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि मुआवज़े के रूप में दी गई है।

» समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण की सुविधा दी गई। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ई-दिशा के माध्यम से नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली राज्य की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में 3 फरवरी, 2015 से शुरू की गई हैं।

» मशरूम की खेती पर 40 प्रतिशत, वर्टिकल खेती पर 65 प्रतिशत व हाइब्रिड सब्जी पौध पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया। मधुमक्खी के बक्से की खरीद पर 85 प्रतिशत और मधुमक्खी पालन के उपकरणों की खरीद पर 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

» दक्षिण हरियाणा के माइनरों में 39 वर्ष बाद तथा प्रदेश की सभी टेलों पर पहुंचा पानी। 243.80 करोड़ रुपए की लागत से 638 जलमार्गों के पुनर्वास का कार्य पूर्ण किया गया।

» अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश के 1,650 अमृत सरोवरों के जीर्णोद्धार के लक्ष्य के फलस्वरूप 1,661 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

अन्य उपलब्धियां

» राज्य में 17 नई स्थायी मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। विभिन्न मंडियों में 59 नई लघु भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने की प्रक्रिया भी प्रगति पर हैं।

» 222 लघु भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित की जा चुकी हैं, जहां विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों द्वारा मिट्टी के नमूने एकत्रित व परीक्षण किए जा रहे हैं।

» मृदा स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए 2410 करोड़ रुपए लागत की प्राकृतिक खेती योजना लागू की गई है। इसके लिए एक प्राकृतिक खेती पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पर अब तक 7,838 किसानों ने पंजीकरण करवाया है।

» किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए गुरुकुल, कुरुक्षेत्र और घरौंडा में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गये हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 4 इम खरीदने पर 3,000 रुपए व देसी गाय की खरीद के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

» किसानों व मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 'अटल किसान मजदूर कैंटीन' योजना के अंतर्गत 25 मण्डियों में कैंटीन शुरू की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 15 अन्य मंडियों में भी कैंटीन जल्द शुरू की जाएगी।

» गन्नौर जिला सोनीपत में 7 हजार करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट निर्माणाधीन है। 150 करोड़ रुपए की लागत से पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर सेब, फल एवं सब्जी मंडी बनाई जा रही हैं तथा इसके 31 अगस्त, 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

» राज्य की 108 मंडियों को 'राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल' (ई-नेम) से जोड़ा जा चुका है।

» 4,740 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़कों के निर्माण पर 1,507 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। 362 करोड़ रुपए की लागत से 740 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

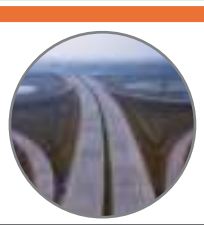

राज्य सरकार ने केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास बादली में जल उपचार संयंत्र के विस्तार की एक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपए है।

प्रदेश के जिन जिलों में गुलाबी सुंडी से कपास की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और साढे 7 हजार से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

शहरी विकास

» तीन हजार करोड़ रुपए से विकसित होंगी नई कॉलोनियां
» स्वामित्व योजना से बड़ी राहत, दमदार आवास योजना

त्योहारी सीजन के शुरू होने से पहले ही हरियाणा में संस्थागत शहरी विकास की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ओर बड़ा कदम उठाते हुए 14 जिलों में 303 कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से नियमित करने की बड़ी घोषणा की है। इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें 39 नगर पालिकाओं की 193 कॉलोनियां और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 110 कॉलोनियां शामिल हैं। शहरी विकास के क्षेत्र में यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इन कॉलोनियों में 2,90,540 संपत्तियां बनी हुई हैं। इससे 10 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।

राज्य सरकार ने ऐसी अनियमित कॉलोनियों की पोर्टल पर जानकारी मांगी थी, उनमें से 1507 कॉलोनी अभी शेष हैं। इनमें 936 शहरी स्थानीय निकाय की हैं और 571 कंट्रोल्ड एरिया में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प हैं कि 31 जनवरी, 2024 तक इन कॉलोनियों को भी नियमित कर दिया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तर पर उपायुक्त एवं जिला नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम अधिसूचना की प्रगति की निगरानी करेगी।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में अनधिकृत कॉलोनियां विकसित न हो, इस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए कठोर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले नियमित की गई कालोनियों में 800 पॉकेट्स नियमित होने से रह गए थे। अब उन्हें भी 31 जनवरी, 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। वर्ष 2014 से लेकर अब तक कुल 1438 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल 874 कालोनियों को नियमित किया गया था।

विकास शुल्क में राहत

प्रदेश के नागरिकों पर एकमुश्त विकास शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा। इसमें राहत देते हुए सरकार ने विकास शुल्क की अदायती को भवन नक्शा, बिक्री अथवा खरीद की मंजूरी आदि से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कि अनधिकृत कालोनियों में सेल डीड पर खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन सरकार ने इसमें रियायत देते हुए 1 जुलाई 2022 से पहले की सेल डीड को मान्यता दे दी है। जिन लोगों ने अपनी सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत करा रखा था, उन्हें बेचा हुआ माना जाएगा। कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल गतिविधियां को भी नियमित करने का निर्णय लिया है।

आवास योजना के तहत 2 लाख आवेदन

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक लाख मकान या प्लाट दिए जाएंगे। इसके तहत पोर्टल पर गरीब परिवार, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है और उनके पास घर नहीं हैं, उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। अभी तक 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है।

उन्होंने बताया कि प्लॉट एक मरले का है, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपए रखी गई है। फ्लैट 450 वर्ग फुट का है, जिसकी कीमत शहर के आधार पर 6 से 8 लाख रुपए रखी गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को बैंकों से ऋण की सुविधा, अधिकतम 20 साल तक, यह भी दिलाई जाएगी। अगले माह तक नीति को अंतिम रूप देकर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

शहरी विकास प्राधिकरण

» स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 930.04 करोड़ रुपए की लागत से 45 परियोजनाएं
» करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 1004.97 करोड़ रुपए की लागत से 94 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
» अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन के तहत 2565 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि अनुमोदित।
» नगर निगमों के महापौर और नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के प्रधान के पद का सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया है।
» प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत स्ट्रीट-वेंडर्स द्वारा 90,781 ऑनलाइन ऋण आवेदन किये गए, जिसमें से 51,894 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये और 46,117 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान किया जा चुका है।
» वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पालिका क्षेत्रों में कुल 1135 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में 10 वर्षों में 874 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया।
» शहरी क्षेत्र के नागरिकों को अपनी समस्याएं, सुझाव व विकास कार्यों से संबंधित मांग के लिए 'नगर दर्शन' पोर्टल शुरू किया गया।
» स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 66,462 व्यक्ति गत 4086 सामुदायिक तथा 6872 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
» कुल 17 शहरी निकाय ओ.डी.एफ़तथा 56 शहरी निकायों को ओ.डी.एफ़के रूप में प्रमाणित किया गया।
» हरियाणा को अक्त़ूबर 2017 में खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।
» गुरुग्राम में 1003 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल सिटी विकसित की जा रही है।
» गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, करनाल एवं पंचकूला में सिटी बस सेवा शुरू।
» गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत में मैट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ऑथोरिटी का गठन किया गया।
» बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने तथा अलॉटियों को समय पर कब्जा दिलवाने हेतु 'हरियाणा रियल एस्टेट ऑथोरिटी' की स्थापना।
» शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्ति यों को ही देने की प्रि या शुरू।
» दीन दयाल जन आवास योजना के तहत छोटे, मध्यम व बड़े शहरों में कुल 387 कालोनियां विकसित करने हेतु 387 लाइसैंस प्रदान किए गए हैं, जिनसे कुल 76,443 आवासिय प्लाटों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा देश का बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है। जल्द ही यह पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाएगी।

स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को अप्रेंटिशिप पर लगाने की शिक्षा विभाग की योजना है ताकि युवा औद्योगिक नगरी में अप्रेंटिशिप कर सकें, वहां हर साल दस हजार की आवश्यकता होती है।

» एक लाख दस हजार युवाओं को सरकारी नौकरी
» बार-बार आवेदन से छूट के लिए संयुक्त पात्र परीक्षा

रोज़गार

सरकारी नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। कौन नहीं जानता कुछ समय पहले तक नौकरियों का वितरण होता था जिसके लिए जन प्रतिनिधियों के कोटे तय होते थे। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए वर्गीकृत किया गया था। नौकरियों के लिए लिखित परीक्षा भी होती थी और साक्षात्कार भी होता था, लेकिन चयन के मापदंड कुछ और ही होते थे।

याद यह भी होना चाहिए कि जब-जब नौकरियां निकलती थीं उनके लिए आवेदन के लिए 200 से एक हजार रुपए तक फीस होती थी और उसकी एवज़ में घर पर चिट्ठी के जरिए बुलावा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उससे थोड़ा और आगे चलें तो जन प्रतिनिधियों के घर व कार्यालय पर नौकरी मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बहुत से आवेदक तो अपने साथ गांव के लोग व खर्ची की पोटली साथ रखते थे। फिर भी किसी की नौकरी लग जाए तो यह उसका सौभाग्य होता था। उस व्यवस्था के चलते पढ़े लिखे युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग निराशा में था।

विगत नौ सालों में ये सब विसंगति वाली परिपाटियां बंद हो चुकी हैं। मनोहर सरकार में नौकरियों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो युवा काबिल होंगे, पढ़े लिखे होंगे उन्हें ही नौकरी पर रखा जाएगा। नौ साल से यही हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि आज युवा पर्ची व खर्ची की बात नहीं करते, परीक्षा के सलेबस की बात करते हैं। न केवल स्कूल कालेजों में बल्कि कोचिंग सेंटरों में युवक व युवतियां जमकर पढ़ाई कर रहे हैं। जन प्रतिनिधियों या पार्टी कार्यकर्ताओं के आगे पीछे अब कोई भीड़ दिखाई नहीं देती।

नौकरी मिलती है योग्यता के आधार पर। प्रसन्ता की बात यह है कि पूरे प्रदेश में पढ़ाई का माहौल लौट आया है। युवा पढ़ रहे हैं, शार्टकट नहीं ढूंढ रहे। जो जितना पढ़ रहा है उसी के अनुसार नौकरी मिल रही है। जिसे नौकरी नहीं मिल रही है राज्य सरकार उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है।

सरकार के उल्लेखनीय प्रयास

- प्रदेश के एक लाख 10 हजार युवाओं को मैरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई।
- भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप-सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त।
- नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारे के लिए एकल पंजीकरण सुविधा।
- बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारे के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान।
- सक्षम युवा योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 3000 रुपए, पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1500 रुपये, 102 पास बेरोजगारों को 900 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घण्टे कार्य करने के एवज में 6000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है।
- बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 32,361 लाभार्थियों को 205 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिये गये।

कर्मचारियों के लिए

- सातवें वेतन आयोग को सबसे पहले लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समकक्ष मातृत्व अवकाश की सुविधा।
- क्लास वन सरकारी अधिकारी से सीधा आईएएस बनने के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग को प्रदेश की ओर से भेजे जाने वाले नामों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से अब लिखित परीक्षा का प्रावधान।
- नई एक्सग्रेशिया स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी के 52 साल की उम्र से पहले निधन होने पर आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नौकरी का प्रावधान।
- सेवा अवधि के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर परिवार को तीन लाख रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान।

» उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई. विभाग
» निर्यात बढ़कर हुआ लगभग 2,45,633 करोड़ रुपये

उद्योग एवं कारोबार

मनोहर सरकार की प्रतिबद्धता एवं सुशासन के चलते प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बना है जिसका परिणाम यह है कि देश विदेश की बड़ी कंपनियों ने निवेश के लिए हरियाणा का रुख किया है। प्रदेश के अलग अलग भागों में उद्योग क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं और बहुत सी कंपनियों के साथ करार हुआ है। जानकारों का मानना है आने वाले समय में हरियाणा उद्योगों का हब होगा। इसके दुरगामी परिणाम यह होंगे कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी।

- उद्यमों के लिए सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम लागू, सभी क्लीयरेंस 45 दिनों के भीतर एक ही पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
- हरियाणा को वैश्विक लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल हब में बदलने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति शुरू की गई।
- नारनौल में 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। इसकी लागत 700 मिलियन अमरीकी डालर होगी। इसे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
- फ्लिपकार्ट द्वारा 285 एकड़ जमीन पर वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्ट हब स्थापित किया जा रहा है। इसमें से 140 एकड़ जमीन पर 1389 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जाने वाला यह क्षेत्रीय वितरण केंद्र एशिया का सबसे बड़ा वितरण केन्द्र होगा। इससे 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
- सोनीपत में फ्लिपकार्ट के नये किरयाना पूर्ति केंद्र के माध्यम से रोजगार के लगभग 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे।
- सोनीपत में, मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 10,000 व्यक्तियों के प्रस्तावित रोजगार के साथ आई.एम.टी खरखौदा में 800 एकड़ भूमि पर एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित कर रही है।
- मेसर्स सुजुकी मोटरसाइकिल को आई.एम.टी खरखौदा में 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे 2000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 2000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- पानीपत में मैसर्स आदित्य बिड़ला समूह को पेंट विनिर्माण सुविधा के लिए औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में 1140 करोड़ रुपये के निवेश और 550 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है।
- पीएम गति शक्ति योजना के तहत भारत सरकार को 6 परियोजनाएं भेजी गई हैं, जिनमें से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।
- पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में ब्लक ड्रग्स पार्क स्थापित किया गया।

एमएसएमई

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में एम.एस.एम.ई. विभाग गठित।
- पदमा स्कीम (वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट) के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास शुरू।
- हरियाणा में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6 लाख 44 हजार 544 उद्यम पंजीकरण प्रमाणित एम.एस.एम.ई हैं। इनमें से 27,370 एम.एस.एम.ई. फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के रूप में पंजीकृत हैं।
- एम.एस.एम.ई के लिए आई.सी.टी. प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र इकाई को 2 साल के लिए 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम 3 लाख रुपए तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- न्यूनतम 5 एकड़ भूमि में फ्लैटेड फैक्टरियां विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत तक अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक सहायता दी जा रही है।
- अनुसंधान एवं विकास केंद्रों व प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए मशीनरी और उपकरण की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत की दर से 5 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उड़ने वाली कार बनेगी

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर अम्बाला में रिंग रोड के आसपास व्हाईब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कारज की फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हुए विनाटा एयरोमोबिलिटी के फाउंडर व सीईओ योगेश रामानाथन ने मुलाकात की।

दुबई से आए योगेश रामानाथन ने अम्बाला में फैक्टरी लगाने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की। रामानाथन ने बताया कि उनकी कंपनी एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाईंग कार को विकसित कर रही है। सीईओ ने बताया हाईब्रिड इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार यानि उड़ने वाली कार है जोकि सड़क पर गतिशीलता का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में आकार ले रही है। उड़ने वाली कारें दुनिया का भविष्य हैं और देश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा फ्लाइंग कार निर्माण की एक फैक्टरी चेन्नई में लगाई गई है जोकि अभी आकार में छोटी है। मगर, कंपनी द्वारा अंबाला में बड़ी फैक्टरी लगाने की योजना है। यह कार जमीन पर भी चल सकेगी और आसमान में उड़ान भर सकेगी।

सीईओ योगेश ने बताया कि कंपनी जो फ्लाइंग कार बना रही है वह हाईब्रिड इलेक्ट्रिकल कार होगी। इसमें आठ फिक्स पिच प्रोपेलर्स, लैंडिंग गियर, इलेक्ट्रिक मोटर युक्त होगी। फ्लाइंग कार की अधिकतम एक घंटे की उड़ान में अधिकतम 350 किलोमीटर दूरी तक भरने की क्षमता होगी। इसे इलेक्ट्रिक मोटर व बॉयोफ्यूल का इस्तेमाल होगा।

6 से 18 साल के बच्चों का परिवार पहचान पत्र से डाटा लेकर शिक्षा के लिए ट्रेकिंग की जाएगी ताकि मार्च 2024 तक स्कूलों में शत प्रतिशत एनरोलमेंट किया जा सके।

हरियाणा पुलिस कर्मियों के बेरोज़गार बच्चों को प्रशिक्षण देने तथा रोज़गार दिलवाने के लिए प्रथम चरण में 147 पुलिसकर्मियों के बच्चों की सूची तैयार की गई है।

बढ़ते गांव-बढ़ता ह

सुविधाओं के मामले में गांव अब कस्बा होने की राह पर हैं। राज्य सरकार की अनेक नीतियों ने गांव को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। पढ़ी लिखी पंचातयों ने तो इन नीतियों के लागू करने में सोने पर सुहागे वाला काम किया है। ग्राम पंचायतों के अधिकारों को विस्तार दिया गया है तथा उन्हें काम करने की आजादी मिली है। इतना ही नहीं गांव के आम लोगों के लिए भी कहने सुनने को ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है जहां वे अपनी शिकायतें या मांग सरकार के सामने रख सकते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर भी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। फिलहाल इस पोर्टल पर 6,197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डेटा उपलब्ध है।

साक्षर एवं सशक्त पंचायती राज व्यवस्था के लिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शिक्षा निर्धारित की गई हैं। सामान्य वर्ग पुरुषों के लिए मैट्रिक तथा अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला पंच का पांचवी पास होना अनिवार्य हैं। पंचायत चुनावों में अपराधिक प्रवृति वाले, जिनके घरों में शौचालय नही हैं, बिजली बिल व सहकारी संस्थानों के बकाया का नियमित भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम अदालत द्वारा घोर अपराधिक मामले, जिनमें कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती हैं, के आरोप निर्धारित किए गए हैं, वे कोर्ट द्वारा माफकिए जाने तक चुनाव नहीं लड़ सकते।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं तथा पिछड़ा वर्ग ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। मतदाताओं को अपने निर्वाचित सरपंच प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार भी दिया गया है।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अंतर्गत 150 गांवों में 641.73 करोड़ रुपए की लागत से 1315 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
- प्रदेश में 57,376 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपये रिवोलविंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक 'डिट लिंकेज प्रदान किया गया है।

हरा-भरा हरियाणा

- प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए राज्य सरकार व अन्य सामाजिक संस्थाओं की ओर से भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं पर्यावरण बचाने में विशेष योगदान कर रही हैं। नहरों का पानी दुषित होने से बचाने के लिए रोहतक में प्रोफेसर जसमेर मलिक उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। सोनीपत के कुछ गांवों में आक्सीवन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
- राजकीय आंकड़ों पर गौर करें तो विगम करीब नौ साल में 16.10 करोड़ पौधे लगाए गए। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से अधिक पुराने वृक्षों को मान-सम्मान स्वरूप 2500 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन का प्रावधान किया गया है।
- औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में 62 हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। मुरथल, जिला सोनीपत में 116 एकड़ जमीन पर तथा यमुनानगर के सढोरा में 11.25 एकड़ पर नगर वनों का विकास किया गया है।
- नगर वन योजना के अन्तर्गत करनाल, पंचकूला, फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा पलवल में नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 34 ऑक्सीवन स्थापित किए जा रहे हैं। कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लम्बी एक नेचर ट्रेल को विकसित की जा रही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व भिण्डावास वन्य जीव अभ्यारण को रामसर साईट घोषित किया गया।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी

- 483 करोड़ रुपए की लागत से 71 मल शोधन संयंत्र शुरू तथा 4 मल शोधन संयंत्र सढौरा, नांगल चौधरी, टोहाना व हिसार निर्माणाधीन हैं।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 490 करोड़ रुपए की लागत से 271 नहर आधारित तथा 229 नलकूप आधारित जलघर स्थापित ।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1457 करोड़ रुपए की लागत से 48 64 नलकूप तथा 1236 बूस्टिंग स्टेशन शुरू।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 3354 करोड़ रुपए की लागत से 19514 किलोमीटर लम्बी पाईप लाईने बिछाई गई।
- महाग्राम योजना के अन्तर्गत 31 बड़े गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक पेयजल आपूर्ति के लिए पेयजल स्त्रोतों में बढ़ोतरी तथा इतने ही गांवों में मल निकासी (सीवरेज) सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए कार्य शुरू किए गए हैं।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर-नल से जल अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिये गये।
- उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग पॉलिसी के तहत गैर पीने योग्य उपयोग के लिए संभावित थोक उपभोक्ता ओं जैसे बिजली संयंत्रों, नगर निगमों, उद्योगों और सिंचाई की पहचान की गई है। इनमें 200 लाख लीटर उपचारित जल प्रतिदिन प्रयोग किया जा रहा है।

सुगम यातायात के लिए सड़कें

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 1130 किलोमीटर लम्बे 20 नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गए हैं। इनमें से 8 राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य पूर्ण तथा 12 का कार्य प्रगति पर।
- दशकों से अधूरे पड़े 135.65 किलोमीटर लम्बे कुण्डली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 2,345 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण।
- प्रदेश में 19,664 करोड़ रुपए की लागत से 32,915 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया गया।
- 2135 करोड़ रुपए की लागत से 2123 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2109 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य 930 करोड़ रुए की लागत से पूर्ण और 387 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य प्रगति पर।
- 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य 1151 करोड़ रुपए की लागत से पूरा। तथा 50 पुलों का निर्माण कार्य 1426 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर।
- हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, पलवल से सोहना-मानेसर-खरखौदा (130 कि.मी. बी.जी. डबल लाईन परियोजना) को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना 5618 करोड़ रुपए की लागत से दिसम्बर, 2025 तक पूरी होगी।
- रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाईन का कार्य 844.15 करोड़ रुपए की लागत से शुरू।
- रोहतक शहर में देश की पहली एलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण।
- कुरूक्षेत्र शहर में एलिवेटेड रेलवे लाईन की परियोजना का कार्य 265.18 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर।
- केएमपी एक्सप्रेस-वे के साथ पृथला (पलवल) से सोनीपत तक 5,566 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली रेलवे लाइन स्वीकृत।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान यातायात को सुगम बनाने के लिए 17 टोल टैक्स बैरियर हटाये गये।
- हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है। इसके विकास के लिए 7200 एकड़ भूमि की पहचान की गई है, प्रथम चरण में 4200 एकड़ क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने पुलिस में इन्फोर्समेंट को बढ़ाया है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 6 प्रतिशत से 11 प्रतिशत की गई है और आगे 15 प्रतिशत करेंगे।

'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' योजना के तहत सौर कृषि पंपों की स्थापना में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा ने कुल 63,733 सौर जल पंप स्थापित किए हैं।

रियाणा

परिवहन

» वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13 बस अड्डों और 2 कार्यशालाओं का निर्माण किया गया। इनके अलावा, 7 बस अड्डों और 5 कार्यशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर।

» हरियाणा राज्य परिवहन के बस बेड़े में 753 पुरानी बसों की जगह नई बसें शामिल की गई। इनके अतिरिक्त , 150 मिनी बसें तथा 18 सुपर लग्जरी बसें भी शामिल की गई।

» गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं में ई-टिकटिंग का शुभारम्भ किया गया।

» हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारियों का वर्दी भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर गर्मियों की वर्दी के लिए 1350 रुपए प्रतिवर्ष तथा सर्दियों की वर्दी के लिए (तीन वर्ष में एक वर्दी) 1450 रुपये किया गया।

» राज्य में संचालित चालक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या अब 22 हो गई है। इनमें 2,61,701 नए भारी वाहन चालक प्रार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

» छात्राओं व महिलाओं के लिए 213 मार्गों पर 181 विशेष बस सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है।

» छात्राओं को अपने घरों से शिक्षण संस्थानों तक 150 कि.मी. की दूरी तक मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

» प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक की आयु) को राज्य की सीमा के अन्दर बस किराए में दी जा रही 50 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर अन्य राज्यों के गन्तव्य स्थान तक कर दिया गया है।

» - किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बस मालिकों से बस किराए पर लेकर संचालन आरंभ कर दिया गया हैं। इस स्कीम के तहत 562 साधारण बसों का संचालन किया जा रहा है।

डिज़िटल कामकाज से आई पारदर्शिता

सीएम विंडो, ट्विटर हैंडल व जनसंवाद

नौ वर्ष के सुशासन में थोड़ा ज़िक्र 'सीएम विंडो' और 'ट्विटर हैंडल' का भी ज़रूरी है। इसी कड़ी में 'जन संवाद' का प्रयोग भी जुड़ गया है।

दरअसल, सरकारी कामों में पारदर्शिता इन तीनों क्षेत्रों का केंद्र बिन्दु है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन तीनों के माध्यम से सफल ि यान्वयन से प्रदेशवासियों में आशा और उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। 'सीएम विंडो' और 'ट्विटर हैंडल' पहल ने इस विश्वास को जन्म दिया है कि सरकार अब उनकी शिकायतों को तुरंत सुनती है, चाहे वह कागज की एक साधारण 'शीट' या कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त की गई हो। इस परिवर्तन का नेतृत्व एक ओएसडी कर रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को बहुत ही कुशलता से वास्तविकता में तब्दील किया है।

2016 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'अंत्योदय' के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा, जो इस बात से अनजान थे कि ये कल्याणकारी कार्य म उनके लाभ के लिए बनाए गए थे और वे ही इनके असली लाभार्थी थे।

इस अवधि में सीएम विंडो के माध्यम से 10 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। अब यह प्रणाली चौपालों, दरवाजों और सभाओं में इस हद तक चर्चा का विषय बन गई है कि लोग निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री की मुक्त कंठ से सराहना करते दिखते हैं।

सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों ने ग़बन की गई राशि को ब्याज सहित जमा कर खुद को सुधारना शुरू कर दिया है जो एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और गांव के सरपंच भी सतर्क हो गए हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके खिलाफ 'सीएम विंडो' पर कोई शिकायत दर्ज न हो। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अब ई-टेंडरिंग को अपनाने की इच्छा व्यक्त की है।

बिना बिचौलिये के सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच रही आमजन की आवाज़ से लोगों ने महसूस किया है कि 'सीएम विंडो' और 'ट्विटर हैंडल' के माध्यम से वे बिना किसी मध्यस्थ या झिझक के अपने विचारों और शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय के एक अधिकारी और एक अवर सचिव 'सीएम विंडो' पर शिकायत समाधान प्रक्रिया की लगातार निगरानी करते हैं और शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट प्रदान करते हैं। 'सीएम विंडो' या 'ट्विटर हैंडल' पर शिकायत अपलोड करने पर शिकायतकर्ता को अगले दिन उनके मोबाइल फोन पर अधिसूचना भी प्राप्त होती है जिसमें उनकी शिकायत के पंजीकरण की पुष्टि होती है। इसके अलावा शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को अग्रेषित कर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है।

आबादी वाले क्षेत्र से शिफ्ट होंगी हाईवोल्टेज लाइनें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को हाईवोल्टेज के खतरे से बचाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। अब घरों, फिरनी, पार्कों, तालाबों, स्कूलों आदि के ऊपर से गुजरने वाली 33,000 वोल्ट्स (केवी) और 11,000 वोल्ट्स (केवी) की बिजली लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा। इस संबंध में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) ने ऐसी सभी लाइनों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे स्वीकृत प्रदान कर दी है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय-2010 (वर्तमान में 2023) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिजली के तारों और ऐसी लाइनों के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसे लाइन शिफ्ट कराने का पूरा खर्च वहन करना होता है। लेकिन सरकार ने लोगों की मांग पर उन्हें राहत देने का निर्णय लिया है।

मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने जनकल्याण के मद्देनजर वर्ष 2016 में घरों के ऊपर से बिजली की लाइनें का अभियान चलाया था, जिस पर 112.17 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था। इसे सरकार ने वहन किया। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने एक बार फिर ऐसा ही अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में हाईटेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए यूएचबीवीएन के 10 सर्कल में 2707 स्थानों पर लाइनों को शिफ्ट करने पर लगभग 96 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 11000 वोल्ट की लाइनों पर 78.35 करोड़ रुपए और 33केवी लाइनों पर 17.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। यूएचबीवीएन में पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर सर्कल शामिल हैं।

इसी प्रकार डीएचबीवीएन के 11 सर्कलों में लाइनों को शिफ्ट करने पर 55 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च का अनुमान है। इस क्षेत्र में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम-।, गुरुग्राम-।।, फरीदाबाद व पलवल शामिल हैं।

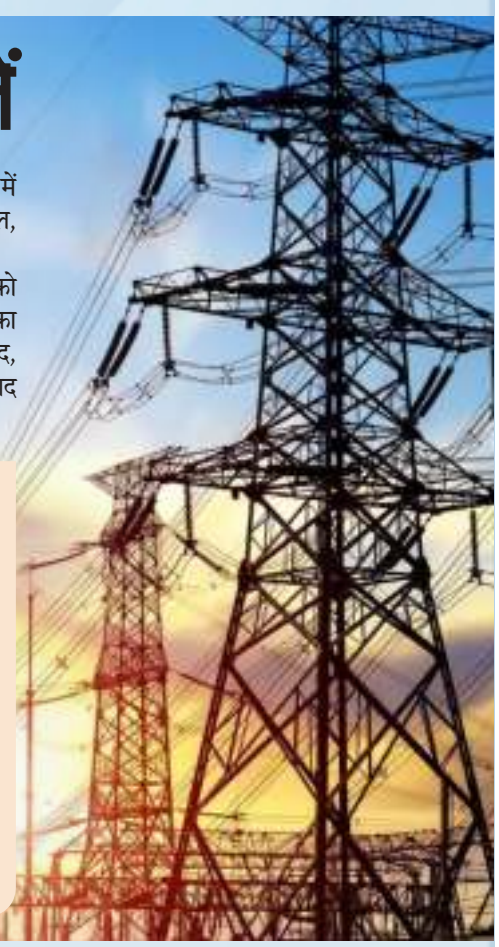

ढाणियों में भी मिलेंगे बिजली कनेक्शन

गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली डेरों-ढाणियों को बिजली के कनेक्शान दिए जाएंगे। यदि अभी भी कोई घर बचता है तो वे सोलर कनेक्शन ले सकते हैं। इस पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। हर घर को बिजली जरूर मिले, इसका प्रावधान राज्य सरकार कर रही है।

300 मीटर तक कोई सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। 300 मीटर के बाद एचटी, एलटी लाइन की जितनी लंबाई होगी, उसके खर्च का केवल 50 प्रतिशत पैसा उपभोक्त ाओं से लिया जाएगा, शेष खर्च निगम वहन करेगा। पहले 150 मीटर के बाद कनेक्शकन का सारा खर्च उपभोक्त ा से लिया जाता था।

बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत-प्रतिशत माफ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पैनल्टी शत-प्रतिशत माफ करने करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को लगभग 8 हजार करोड़ रुपए का सीधा लाभ होगा। इसके अलावा, बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 15 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इस प्रकार संपत्ति मालिकों को छूट मिलने के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

हरियाणा प्रदेश में 2014-15 में 215 गौशालाएं थीं जो कि अब बढ़कर 649 हो गई है। वर्तमान में गौशालाओं में लगभग साढ़े 35 हजार गौवंश हैं।

अंबाला छावनी में आरसीएस उड़ान योजना के तहत डोमेस्टिक एयरपोर्ट को सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसकी स्थापना से आस-पास के क्षेत्र में व्यवसाय व रोजगार के अवसर बढ़ेंगें।

लोक साहित्य में देसी नुस्ख़े

मौसम बदल रहा है, सेहत में उतार चढ़ाव संभव है। शरीर को प्रकृति के अनुसार ढलना होता है तो उसके लिए कुछ शारीरिक परिवर्तन अवश्यंभावी माना जाता है। हरियाणवी लोक साहित्य विभिन्न विषयों के मर्म से सुसज्जित है। मौसम के अनुसार खानपान पर अनेक रचनाएं गढ़ी गई हैं। लोकोक्ती व मुहावरों में वर्णित इन रचनाओं में जो गढ़ा गया होता है उसके पीछे लंबे अरसे का अनुभव छुपा होता है। प्राचीन काल में जब आधुनिक चिकित्सा इतनी समृद्ध नहीं हुई थी तो आंचलिक लोक जीवन इन्हीं रचनाओं पर भरोसा कर स्वास्थ्य लाभ लेता था। आज के जीवन में बेशक इनकी अहमियत कम हो गई हो लेकिन कई मामलों में आज भी इनकी प्रासंगिकता से इंकार नहीं किया जा सकता।

कहावतों में साफ पानी पीने के बारे में इस प्रकार हिदायत दी गई है कि 'पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जानकर'। भोजन करने के बाद सैर करने की शिक्षा भी हरियाणवी कहावत के माध्यम से इस प्रकार दी गई है कि 'सौ पग चले, खाय के जोई, उसको वैद्य, न बुझे कोई।' यानी जो आदमी भोजन करने के बाद सौ पग सैर करता है, वह कभी बीमार नहीं होता। खान-पान एवं आहार संबंधी एक अन्य कहावत में कहा गया है- खाओ मन भाता, पहरो जग भाता।

हरियाणा के लोगों के खान-पान में रोटी की मुख्य भूमिका है, इसको कहावत के माध्यम से इस प्रकार कहा गया है कि 'सो बार सत्तू, नौ बार चबीना। एक बार रोटी लेणा न देणा।' हरियाणा में खिचड़ी को - सुपाचक भोजन माना जाता है। इस बारे कहा गया है कि 'खिचड़ी के च्यार यार। घी, पापड़ी, दही, आचार'। परंतु इसके विपरीत अरबी की सब्जी को पूरी के साथ खाने की सख्त मनाही है। इसका वर्णन कुछ यूं किया गया है कि 'जाको मारया चाहिये, बिन लाठी मर जाये। वांको यही बताइये, अरबी पूरी खाय'। अल्पाहारी सदा सुखी, उचित माना गया है।

इस बात को एक अन्य कहावत में इस प्रकार भी कहा गया है-

आसोज प्यारी घिया, तौरी, कातक प्यारी दही-मट्ठा।
मंगसर प्यारी कचरी, डांठल, गाजर बाजरा, बथूआ।
पौह प्यारा गंडा, गुड़, आलू, तिलकुटी और टैओथा।
माह प्यारी गौज्जी-खिचड़ी, फागुण प्यारा मजाक-ठठा।
चैत प्यारी कनक, काकड़ी, कोला, कद्दू
बैसाख प्यारा मेसा, ठण्डा, बैंगन, भर्था।
जेठ प्यारी ठण्डाई, राबड़ी, सत्तू, प्याज, निद्दा ।
साढ़ प्यारा नींबू, नमक, आम टपका ।
सावण प्यारी सुहाली, पेड़े, गुटगालटी, पूड़े, खीर।
भादुआ प्यारा दलिया, शक्क र, चौले, भिंडी, टिण्डे, घाटा।

समयानुकुल सादा, सुपाचक एवं शाकाहारी खान-पान, सात्विक दिनचर्या, सकारात्मक सोच एवं संयमी जीवन- शैली अपनाकर हम दीर्घायु जीवन पा सकते हैं, इसलिए एक कहावत में कहा गया है कि जान है तो जहान है। हरियाणवी लोक साहित्य में दैहिक सौन्दर्य के लिए भी अनेक नुस्खों का प्रयोग किया गया है। दही, मक्खन एवं केसर को मिलाकर होंठों पर लगाने होठों का रंग गुलाबी हो जाता है।

आयुर्वेद की परम्परा के अनुसार लोकजीवन में ये दोहे प्रचलित हैं-

अजवाइन को पीसिये, गाढ़ा लेप लगाय,
चर्म रोग सब दूर हो, तन कंचन बन जाये।
थोड़ा सा गुड लीजिए, दूर रहे सब रोग,
अधिक कभी मत खाइए, चाहे मोहन भोग
अजवाइन और हींग लें, लहसुन तेल पकाय
मालिश जोड़ों की करें, दर्द दूर हो जाय।
ऐलोवेरा- आंवला, करे खून में वृद्धि
उदर व्याधियां दूर हों, जीवन में हो सिद्धि ।
मधु का सेवन जो करे, सुख पावेगा सोय,
कंठ सुरीला साथ में, वाणी मधुरिम होय ।
पीता थोड़ी छाछ जो, भोजन करके रोज,
नहीं जरूरत वैद्य की, चेहरे पर हो ओज ।
ठण्ड अगर लग जाय जो नहीं कुछ काम,
नियमित पी लें गुनगुना पानी दे आराम।
कफ से पीड़ित हो अगर, खाँसी बहुत सताय
अजवाइन की भाप लें, कफ तब बाहर आय।
छाछ हींग सेंधा नमक, दूर करे सब रोग,
जीरा उसमें डालकर पियें सदा यह भोग।

-साभार

सांझी

आश्विन मास के शुक्ल प्रथमा से दशमी तक हरियाणा के लोकजीवन में 'सांझी' की पूजा होती है। बालिकाएं इसकी स्थापना घर की किसी दीवार पर करती हैं। स्थापना के पूर्व से ही सांझी के सभी अंग-प्रत्यंग बना लिए जाते हैं और फिर इन्हें गोबर की सहायता से दीवार पर स्थापित कर दिया जाता है। दस दिन बालिकाएं इसकी पूजा करती हैं तथा विजयदशमी के दिन इसका समापनोत्सव मनाया जाता है। उस दिन सांझी को उतार कर निकट के किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

सांझी थेपने से पूर्व कन्याएं मिट्टी के चांद, सितारे, श्रृंगार के उपकरण (कथी, कंठी, टीका, आंगी, तागड़ी, घाघरी, डूगे, कंगन, हथफूल, कड़ी छलकड़े) आदि का निर्माण कर उन्हें सुखा लेती हैं। इसके बाद लगाने से पहले इन सभी उपकरणों को सफेदी व गेरुए रंग से रंग लिया जाता है। अमावस्या के दिन गाय के गोबर की सहायता से सांझी के उपकरणों को आंगन की किसी दीवार पर चिपका कर एक नारी आकृति बना ली जाती है। इसके दांत चावलों के दानों से बनाए जाते हैं, जिसे 'घूंधा' के नाम से जाना जाता है। सांझी लगाते समय कुंवारी कन्याएं सांझी से प्रश्न करती है कि वह क्या पहनेगी, क्या ओढ़ेगी, किस चीज की मांग भरवाएगी? उसके उत्तर में सांझी मिसरू, स्यालु और मोतियों की मांग करती है। सांझी लगाते समय गांव की औरतें अक्सर ये गीत गाती हैं-

जाग सांझी जाग तेरे माथे लाग्या भाग,
पीली-पीली पट्टियां सदा सुहाग।
मेरी सांझी के ओर-थोरे चोलां की मुट्ठी,
हे में तन्नै बुझं सांझी कै तोल्या की गुंट्ठी ।
हे मेरे बाप घड़ाई बहना, बीरण मोल चुकाई,
बेबे नौ तोल्यां की गूंट्ठी ।

- संवाद ब्यूरो

सुण छबीले बोल रसीले

बिना दुभात-सबका विकास

- छबीले दशहरा आग्या।
- हां तो फेर, यू तो हर बरस आवै सै। नई बात के सै?
- नई बात तो कोन्या, पर मन खराब होज्या सै।
- क्यांतै, मन पै के बिजली पड़गी?
- दशहरा आए साल आवै सै। लोग इसनै किसे न किसे तरियां मनावैं भी सैं। चाहे वे आपणे घरां चावल-बूरा जीमते हों या रावण दहन देखण बाहर जाते हों। मेरा सवाल यू सै अक दशहरा जिस बात के लिए मनाया जा सै लोगां नै उस बात पै खरा तो उतरणा चाहिए।
- सीधा-सीधा बक, कुलड़ी में गुड़ मत फोड़ै।
- मेरा मतलब यू सै अक लोग दशहरे के मौके पर आपणी बुराइयां नै क्यूं नहीं त्यागते?
- रसीले, पहल्यां आपणे कुड़ते में झांक। तूं कुणसा धर्मात्मा सै। पहल्या आपणी बुराई तो त्याग ले।
- छबीले मेरे में कोय बुराई कोन्या।
- यू गलतफहमी हर इंसान में हो सै। सोलहा कला संपूर्ण कोय कोन्या।
- क्यूं भाई बता मेरे में के कमी सै?
- के जरुरत थी मेरी बहू तै न्यू कहण की अक दारू पीण खातिर मनैं तेरे तैं दो सौ रुपए लिये थे?
- लिए तो थे छबीले, इसमें झूठ के सै?
- बावली तरेड़, तेरे आगे मनै दारू खरीदी थी? दो सौ रुपए लेकै शहर गया था। सौ रुपयां का बाइक में तेल घलवाया और 50 रुपयां के तेरी भाभी खातिर गोल गप्पे ल्याया। अर न्यू बता तनै कब देख लिया मैं दारू पीता। दारू कै तो मैं हाथ भी ना लगाया करता।
- अरै तूं तो नाराज होग्या, मैं तो भाभी गैल्यां मजाक करूं था। आखिर मजाक भी तो कोई चीज होती होगी। मजाक ना करैंगे तो जीणा भारी होज्यागा। समझा कर। बता, शहर के करण गया था?
- कृषि विभाग में गया, खेत की माटी की जांच करवाणी देकै आया, और घर के पाणी का सैंपल देकै आया। ताकि उनकी जांच होज्या। बागवानी विभाग आल्यां तै बात करकै आया अक उनके खेत में कौन कौन से पेड़ लाए जा सकैं सैं? इस धान की खेती तै जी भर लिया। पानी इतणा होता नहीं, जुगाड़ तुगाड़ करैं भी तो खर्चे मुश्किल तैं पूरे हो सैं। इसा काम देखूं सूं अक पेड़ भी लागज्यां और गेहूं की फसल भी होज्या।
- वा भाई छबीले। तूं तो काम का माणस सै। दो सौ रुपया में घणे काम काढ़ आया।

- रसीले, सरकार नै खेत क्यार खातिर स्कीम तो बोहत चला राखी सैं। पर लोग ध्यान ना देते। लोग न्यू चाहवैं सैं अक घरां बैठे सबकुछ आज्या। काम ना करणा पड़ै। ईब मंडोरियां नै देख ले। कई भाई सैं। लेबर की बाट में धान खेत में खड़े-खड़े खराब होण लाग रे सैं। पर खुद काटण की हिम्मत ना राखते। सारे दिन गाम में कदे उड़ै सी, कदे उड़ै सी राजनीति पै बहस करे जा सैं।
- उननै बालक कानून मंत्री भी कहैं सैं। करणा-धरणा कुछ नहीं, रौला ए रौला। उनके तो बालक भी उनै बरगे सैं। कोई खेत क्यार में जाकै राजी कोन्या। पढ़ाई लिखाई तै दूर।
- अरै रसीले, यो तो भला हो इस मनोहर सरकार का। जिब तैं पढ़े लिखे बालक नौकरी लागण लागे सैं, गामां का माहौल ए सुधरग्या। ना तो गामां का पूरा आवा का आवा खराब हो लिया था। एकाध बालक पढ़या करता। जो पढ़या करता वो बाहर चल्या जा था। ईब तो नौकरी लागण खातिर दुनिया के बालक पढ़ण लाग गे। ये कानून मंत्री जिसे तो बहुत कम सैं जो फोकट की खाणा चाहवैं सैं।
- भाई छबीले, इस सरकार में एक बात देखी। किस्से मामले में कोई दुभात कोन्या होती। चाहे वो गरीब हो या ठीक ब्यौंत आला। सबको एक नजर तैं देख्या जा सै। पहल्यां की तरियां लूट खसोट कोन्या। जिनके फर्जी बीपीएल कार्ड बनणे रे थे वे सही काटे और जिनके नहीं बणरे थे और बणने चाहिएं थे उनके बणाए। एंडी काम कर्‌या सरकार नै। और देख म्हारे हलके नै कदे इस सरकार का एमएलए नहीं बणाया। फेर भी गाम में 18 से 24 घंटे बिजली आवै सै। सड़क देख ले। इसी सड़क पड़ौसी हलके की कोन्या। एकाध सड़क छोड़कै सारे सड़क मार्ग बढ़िया बणा राखे सैं। गाम की पीएचसी में चले जाओ। डाक्टर भी मिलैं सैं और दवाई भी। सारी दवाई फ्री में। काल तो मैं दांत का इलाज कराकै आया, बिलकुल फ्री। शहर में चला जाता तो हजार रुपए खराब हो ज्याते।
- भाई रसीले, मनोहर जिसा सीएम पहल्यां कदे नहीं देख्या। जुबान का धनी और संकल्प का पक्का। जो कह दिया सो कह दिया। झूठ का कोई मतलब नहीं। सारा परदेश एक परिवार मान राख्या सै। बस एक धुन सवार सै अक इस परदेश ताहीं इसी पक्की व्यवस्था दे दी जावै जिसतैं लोगां नै आगे चालकै कोई तकलीफ ना हो। साफ सुथरी व्यवस्था, साफ सुथरे लोग। ना कोई आपाधापी, ना कोई रोग।
- आच्छा तो नेम कर, इस दशहरे पै आपणी सारी कमजोरियां छोड़ देगा। लोगां गेल्यां मजाक बेशक कर पर किसे की चुगली ना कर। ले, ये लाड्डू खा। वो रामफल बांटता आवै था। उसकी छोरी एचसीएस लागी सै।

– मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com